भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2428

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

आयात पर निर्भरता कम करने हेतु कोयला गैसीकरण का विस्तार

2428. श्री कार्तिकेय शर्मा**:**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आयातित प्राकृतिक गैस, मेथेनॉल, अमोनिया और यूरिया को प्रतिस्थापित करने के लिए कोयला गैसीकरण और कोयले-से-रसायन उत्पादन को बढ़ाकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने और आयात पर निर्भरता कम करने का प्रस्ताव रखती है;

(ख) इस परिवर्तन से कितने आयात मूल्य की बचत अनुमानित है तथा देश के लिए इससे कौन-कौन से लाभ अपेक्षित हैं;

(ग) अब तक हुई प्रगति का, गैसीकरण परियोजनाओं के लिए चिन्हित क्षेत्रों एवं कोयला ब्लॉकों का ब्यौरा क्या है तथा राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन के अंतर्गत कौन-कौन से प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं; और

(घ) आगामी वर्षों के लिए गैसीकृत कोयले के संबंध में निर्धारित रूप-रेखा एवं लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) और (ख) : भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए, सरकार कोयला गैसीकरण को बढ़ावा दे रही है और उसने कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए दो वित्तीय प्रोत्साहन स्कीमों को मंजूरी दी है, जिनमें से एक जनवरी, 2024 में 8,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ और दूसरी स्कीम मई, 2026 में 37,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्वीकृत की गई है। पहली स्कीम के तहत, आठ (8) कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। शुरू होने पर, इन परियोजनाओं से अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (एसएनजी), मेथनॉल, यूरिया, एसिटिक

एसिड और डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआई) जैसे उत्पादों पर आयात निर्भरता कम होने की अपेक्षा है। इन परियोजनाओं से आयात प्रतिस्थापन के माध्यम से वार्षिक लगभग 16,500 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होने का अनुमान है।

(ग) : 8,500 करोड़ रुपये की स्कीम की तीन श्रेणियों के तहत अनुमोदित आठ (8) परियोजनाओं के लिए निर्धारित वित्तीय प्रोत्साहन का विवरण निम्नानुसार है:

श्रेणी	**स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निर्धारित वित्तीय सहायता**	**संवितरित वित्तीय सहायता**
श्रेणी-I	3 परियोजनाओं में ₹4,050 करोड़ (प्रत्येक परियोजना के लिए ₹1,350 करोड़)	शून्य
श्रेणी - II	3 परियोजनाओं में ₹1,983.06 करोड़	वित्त वर्ष 2026 में जेएसएल को ₹235.52 करोड़ संवितरित किए गए
श्रेणी - III	2 परियोजनाओं में ₹200 करोड़ (प्रत्येक परियोजना के लिए ₹100 करोड़)	शून्य
कुल	**8 परियोजनाओं में ₹6,233.06 करोड़**	**₹235.52 करोड़**

8,500 करोड़ रुपये की स्कीम के तहत स्वीकृत कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए चिन्हित की गई खानों का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	**कंपनी**	**राज्य**	**चिन्हित कोयला ब्लॉक/खानें**
श्रेणी - I	भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड	ओडिशा	एलबीएल खान, लखनपुर, एमसीएल
	कोल गैस इंडिया लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	सोनपुर बाज़ारी, ईसीएल
	प्रस्तावित सीआईएल-बीपीसीएल संयुक्त उद्यम	महाराष्ट्र	बोर्डा यूजी, तकली जेना ओसी, डब्ल्यूसीएल
श्रेणी - II	जिंदल स्टील लिमिटेड	ओडिशा	उत्कल सी, उत्कल -बी 1, बी 2
	ग्रेटा एनर्जी एंड मेटल प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र	बोर्डा खान, डब्ल्यूसीएल
	न्यू इरा क्लीनटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र	भांडक-पश्चिम बोर्डा, डब्ल्यूसीएल
श्रेणी - III	न्यू एरा क्लीनटेक	महाराष्ट्र	भांडक-पश्चिम बोर्डा, डब्ल्यूसीएल

	सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड		
	कार्तिकेय वायुनंदन प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा चिन्हित किया जाना है

(घ) : राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन के अंतर्गत सरकार ने वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन (मि.ट.) कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 8,500 करोड़ रुपये की स्कीम के तहत लगभग 22.6 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) कोयला गैसीकरण क्षमता वाली परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जबकि दिनांक 13.05.2026 को अनुमोदित 37,500 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रोत्साहन के साथ नई स्कीम से कोयले की लगभग 75 एमटीपीए गैसीकरण क्षमता बढ़ने की अपेक्षा है।

****